Q. No. 03

सार्वजनिक ऋण के भार से आप क्या समझते हैं? सार्वनिक ऋण का भार कौन वहन करता है? :– वर्तमान पीढ़ी या भावी पीढ़ी ?

What do you mean by the burden of public debt? who bears- the burden of public debt present generation or feature generation.

Ans - सरकार जब अपने आप के ऊपर जय के अतिरेक (Surplus) के पुरा करने के लिये जो रकम उधार लेती है उसे सार्वजनिक ऋण कहाँ जाता है।

Pd –E-R

जहां E= सार्वजनिक व्यय

R= सार्वजनिक आय

L= सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक अधिकारियों की आय प्राप्ति का एक तरीका सार्वजनिक ऋण भी होता है, लेकिन उपरोक्त समीकरण में R के अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण शामिल नहीं किया गए हैं। सरकार बैंकों से निजि व्यक्तियों से व्यवसायिक संस्थाओं से एवं अन्य संस्थाओं से ऋण ले सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार देश के अन्दर या देश के बाहर से भी ऋण ले सकती है। : विदेशियों से लिये गये ऋण को बाह्य ऋण भार कहो जाता है। सरकार दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करे करने के लिए ट्रेजरी बिलस विलय जारी करती है। जिसमें धारकों को मूलधन एवं ब्याज की अदायगी का वादा होता हैं।

BURDEN OF PUBLIC DEBT

ऋणों को चुकाने के लिय लोगों पर कर लगाती है। कर लगाने से लोगों को न्याय करना पड़ता है। एवं इसका अन्य प्रभाव भी अर्थ व्यवस्था पर पडता है। लोगों के द्वारा किए जाने वाले त्याग एवं आर्य व्यवस्था पर पड़ने वाले कुप्रभाव को ही सार्वजनिक ऋणभार कहा जाता हैं।

सार्वजनिक ऋण के निम्नलिखित प्रकार के भार होते हैं।

1) मौद्रिक भार (Money Burden) –मौद्रिक भार को सार्वजनिक ऋण का Primary burden भी कहा जाता है। सार्वजनिक ऋण का ब्याज चुकाने के लिय सरकार कर लगाती है या वर्तमान करो की दरों में वृद्धि करती है, जिसके जिससे लोगों के मौद्रिक आय घट जाती है। करदाताओं के मौद्रिक आय में उस कमी को ही मौद्रिक भार कहा जाता है।

(2) **वास्तविक भार (Real Burden):** → सार्वजनिक ऋण के वास्तविक भार को (Secondry burden) माध्यमिक बार भी कहा जाता है। सार्वजनिक ऋण को चुकाने के लिय सरकार जब

ऊँची दर पर कर लगाती है तो इसका कुप्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है तो इसका कार्य करने एवं बचत करने की क्षमता एवं इच्छा घट जाती है!

(3) **प्रत्यक्ष भार (Direct Burder):—→** मौद्रिक भुगतान को प्रत्यक्ष मौद्रिक भार कर वास्तविक भार आर्थिक कल्याण के भार चुकाने के लिए किय गये कहा जाता है जबकि प्रत्यक्ष समाज के द्वारा किए गए त्याग को कहा जाता हैं।

(4) **अप्रत्यक्ष भार (Indirect burden):—** वास्तविक ऋणों को चूकाने के लिए करों में वृद्धि करने से उत्पादन पर जो प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है, उसे सार्वजनिक ऋण का अप्रत्यक्ष भार कहा जाता हैं।

राज्य जब सार्वजनिक ऋण लेती है तो इसका भार देश पर पड़ता है। अब हम यह जानना चाहते है कि सार्वजनिक ऋण का बोझ वर्तमान पीढ़ी पर पडता हो! या भावी पीढ़ी पर इस सम्बन्ध में दो बातो को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है a. क्या कर्ज के रकम को प्राप्त करने से भावी पीढ़ी पर आवश्यक रूप से बोझ पड़ता है। b. क्या सार्वजनिक ऋण का बोझ भावी पीढ़ी पर विस्थापित किया जा सकता हैं।

परम्वादी अर्थशास्त्रियों का विचार है कि सार्वजनिक ऋण का भार भावी पीढ़ी पर विस्थापित नहीं किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में देखा जाय तो भावी पीढ़ी को भी सार्वजनिक ऋण का कुछ भार वहन करना पड़ता है। 18वी शताब्दी में 'अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक ऋण को उचित माना था। क्योंकि उन्हें राज्य की आर्थिक क्रियाओं पर पूर्ण— विश्वास था, लेकिन 19वीं सदी एवं 20वीं सदी के प्रारम्भ में अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक ऋण को उचित नहीं माना क्योंकि वे देश की आर्थिक क्रियाओं में राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। वे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। क्योंकि उस समय में राज्य की आर्थिक क्रियाओं के सम्बंध में सरकार पर पुर्ण विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक जो अन उत्पादक होता है। बाद में Malthus J.S Mill आदि अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक ऋण के सम्बन्ध में उदारवादी दृष्टि कोण अपनाया।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार सार्वजनिक ऋण के कारण कोई प्रारम्भिक वास्तविक बोझ भावी पीढ़ी पर नहीं पड़ता। सार्वजनिक ऋण का भार उस समय पडता है। जब सार्वजनिक ऋण प्राप्त किया जाता है। इसलिए यह वर्तमान पीढ़ी पर बोझ डालता है। सार्व— जनिक ऋण के कारण भावी पीढ़ी एवं वर्तमान पीढ़ी के बीच कोशों का स्थानान्तरण होता है। करदाताओं के बच्चों को कर का जिम्मेवारी वहन करना पड़ता है जबकि ऋणदाता के बच्चे सम्बन्धित सम्पति प्राप्त करते है इस प्रकार की करदाताओं का न्याय बॉड धारकों के लाभ के बराबर हो जाता है। इस प्रकार पूरे समाज में शुद्ध भार शून्य हो जाता है। इसलिए आन्तरिक ऋण का कोई भार अर्थ व्यवस्था पर नहीं पड़ता हैं। इसलिए कुछ अर्थशात्रियों का विचार है। कि आंतरिक ऋण को ऋण नहीं समझा जाना चाहिए एवं आन्तरिक ऋण के कारण भावी पीढ़ी पर किसी बोझ का विस्थापन नहीं होता हैं।

सार्वजनिक ऋण का भार वर्तमान पीढ़ी पर पड़ेगा या भावी पीढ़ी पर पडेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार को ऋण बचत को घटकर दिया गया है या उपयोग

को धटाकर अगर सार्वजनिक ऋण से बचत–नहीं होता है तो पूंजी निर्माण घटेगा एवं विनियोग भी घटेगी। इससे भावी पीढ़ी की उत्पादकता घट जाएंगी। अतः ऐसे सार्वजनिक ऋण का बोझ भावी पीढ़ी पर पड़ेगा। इस विचार से LERNER AND SAMUELSON दोनों सहमत है सार्वजनिक ऋण से वर्तमान पीढ़ी को या तो उपयोग या बचत दोनों को घटाना पड़ता है।

बचत घटने से भावी पीढ़ी प्रभावित होगा, उपयोग घटो से बर्तमान पीढ़ी प्रभावित होगा। इस प्रकार अगर वर्तमान – पीढ़ी उपयोग को नहीं धटाती है तो इसका यह मतलब है कि वे सार्वजनिक ऋण का बोझ भावी पीढ़ी पर विस्थापित करना चाहते है।

अब यह प्रश्न है कि अगर 'विकास के लिए आवश्यक रकम करों के माध्यम से प्राप्त किया जाय तो वर्तमान पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा। क्योंकि इससे उपयोग में कमी होती है लेकिन अगर आवश्यक रकम की प्राप्ति सार्वजनिक ऋण की माध्यम से की जाय तो इसका प्रभाव भावी पीढ़ी पर पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान पीढ़ी सामान्यतः अपने बचत से ही सरकार को कर्ज देती है। अगर सार्वजनिक ऋण से आय प्राप्त किया जाय तो ऋणदाताओं को सरकारी भवन प्राप्त होते है। जिसे सम्पति माना जाता है लेकिन अगर लोगों पर कर लगाया जाय तो लोगों की आय में शुद्ध कमी होती है। यह आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक ऋण का बोझ हमेशा भावी पीढ़ी पर ही पड़ेगा। BUCHANAN का विचार यह है कि वर्तमान पीढ़ी में जो बौंड का धारक होते है वे सरकार को अपनी इच्छा से कर्ज देते हैं। इसलिए अगर किसी प्रकार के चार का प्रश्न नहीं उड़ता हैं। लेकिन भावी पीढ़ी पर बोझ इसलिय पडेगा कि उन्हें आवश्यक रूप से करों का भुगतान करना पडेगा।

उपरोक्त विश्लेषण में सिर्फ सार्वजनिक ऋण के बोझ की व्याख्या व्याख्या की गई है लेकिन इस बात कि व्याख्या नही कि गई है कि सार्वजनिक ऋण का प्रयोग जो देश के विकास के लिए किया जाएगा। उसका अनुकूल प्रभाव अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है। अगर सार्वजनिक ऋण से पूंजी निर्माण में वृद्धि कि जाय एवं विनियोग को बढ़ाया जाय तो इससे देश का आर्थिक विकास होगा। इसलिए यह कहना उपायुक्त नहीं है कि सभी सार्वजनिक व्यय हमेशा अन–उत्पादक होते है।

अगर वाह्य ऋण लिया जाय तो इसका प्रभाव भावी पीढ़ी पर पड़ सकती है क्योंकि सार्वजनिक वाह्य ऋण से देश के साधनो में वृद्धि होती है एवं भावी पीढ़ी को ऐसा कर्ज चुकाना पड़ता है। अगर वाह्य ऋण से जो भी उत्पादकता में वृद्धि की जाय तो भावी पीढ़ी भी ऐसे ऋण के बोझ का अनुभव नहीं करेगे जबकि भावी पीढ़ी को ही बाह्य ऋण चुकाना पड़ता है।